

कृषि पूंजी में गरिावट: कारण एवं समाधान

यह एडिटरियल 21/12/2023 को 'हद्वि बज़िनेसलाइन' में प्रकाशित ["Agri capex, a black box"](#) लेख पर आधारित है। इसमें कृषि में सकल पूंजी निर्माण में गरिावट के मुद्दे पर चर्चा की गई है।

प्रलिमिस के लिये:

[सूक्ष्म सचिाई, राष्ट्रीय कृषि विकास योजना \(RKVY\), किसान क्रेडिट कार्ड, ब्याज सहायता योजना, भांडागारण विकास और नयामक प्राधकिरण, प्रधानमंत्री किसान संपदा योजना, कृषि-बाज़ार अवसंरचना नधि, परंपरागत कृषि विकास योजना, कृषि उड्डान, हरति जलवायु कोष \(GCF\)।](#)

मेन्स के लिये:

कृषि में सकल पूंजी निर्माण में कमी, GCAF में इस कमी का प्रभाव, GCAF को बढ़ावा देने के लिये सरकारी पहल और आगे की राह।

कृषि में पूंजी निर्माण की स्थिति बहस का वषिय रही है। कृषि में सकल पूंजी निर्माण (Gross Capital Formation in Agriculture- GCFA) वर्ष 2013-14 से घटता जा रहा है। कृषि और संबद्ध क्षेत्रों के सकल घरेलू उत्पाद के प्रतिशत के रूप में **GCFA वर्ष 2013-14 को समाप्त हुई तीन वर्ष की अवधि में 17.5% से घटकर वर्ष 2020-21 को समाप्त हुए तीन वर्ष की अवधि में 15.7%** रह गया।

कृषि क्षेत्र में सकल पूंजी निर्माण में कमी क्यों आ रही है?

- समग्र अर्थव्यवस्था में ही पूंजी निर्माण में मंदी की प्रवृत्ति निज़र आ रही है, लेकिन कृषि में मंदी की दर अधिक तीव्र है।
 - वर्ष 2004-05 से **2013-14 की अवधि के दौरान GCF और GCFA दोनों की चक्रवृद्धि वार्षिक वृद्धि दर (CAGR) 9%** रही।
 - लेकिन **2013-14 से 2020-21 की अवधि में GCFA का CAGR तेज़ी से गरिकर 3%** हो गई है, जबकि GCF में 5% की कुछ अधिक दर दर्ज की गई।
- GCFA का कृषि के भवषिय के विकास पर महत्त्वपूर्ण प्रभाव पड़ेगा और इसलिये इस मंदी के संभावित कारणों को समझना ज़रूरी है।

इस मंदी के पीछे क्या कारण हैं?

- सार्वजनिक निविश में संरचनात्मक बदलाव: एक मान्यता यह है कि सार्वजनिक निविश में गरिावट प्रमुख और मध्यम सचिाई परियोजनाओं से सूक्ष्म सचिाई की ओर स्थानांतरित होने के कारण हुई है।
 - कृषि क्षेत्र में 90% से अधिक सार्वजनिक निविश सचिाई से संबंधित है और संभव है कि ध्यान क्षेत्र में बदलाव के कारण समग्र पूंजी निर्माण में गरिावट आई हो।
- RKVY कार्यक्रम में बदलाव: राष्ट्रीय कृषि विकास योजना (RKVY) ने कृषि में राज्य निविश को बढ़ावा देने में महत्त्वपूर्ण भूमिका निभाई।
 - वर्ष 2014 के बाद से, **चूँकि राज्य RKVY के व्यय का 40% पूरा कर रहे थे**, इस आवश्यकता में ढील दी गई। इसने राज्यों के लिये कृषि में साल-दर-साल निविश जारी रखने की प्रोत्साहन संरचना को कमज़ोर कर दिया है।
- कृषि क्षेत्र से अपवर्जन: ग्रामीण वदियुतीकरण, बजिली आपूर्ति, ग्रामीण सड़क, भंडारण, कृषि अनुसंधान, उर्वरक और कीटनाशक उद्योगों पर महत्त्वपूर्ण व्यय को कृषि या संबद्ध क्षेत्रों के अंतर्गत वर्गीकृत नहीं किया गया है।
 - संभव है कि इस अपवर्जन से कृषि विकास में इन क्षेत्रों के समग्र योगदान को चहिनति करने में अंतराल उत्पन्न हुआ हो।
- नज़ी निविश में कमी: कृषि क्षेत्र में 80% से अधिक निविश नज़ी क्षेत्र द्वारा किया गया है। कृषि में व्यापार स्थिति (Terms of Trade- ToT) कृषि में नज़ी निविश का एक महत्त्वपूर्ण निर्धारक है।
 - ToT किसानों द्वारा प्राप्त कीमतों को दर्शाता है और हाल की अवधि में इसमें व्यापक गरिावट आई है।
 - संभव है कि ToT में इस गरिावट ने कृषि में नज़ी निविश को भी कम कर दिया हो।
 - नज़ी क्षेत्र के निविश, जो कृषि में महत्त्वपूर्ण योगदान देते हैं, ToT से प्रभावित होते हैं।
- कृषि पद्धतियों में बदलाव: संभव है कि सूक्ष्म सचिाई जैसे अधिक आधुनिक एवं कुशल तरीकों की ओर कृषि पद्धतियों के बदलाव ने पूंजी निविश के प्रकार एवं पैमाने को प्रभावित किया होगा।

- **आर्थिक और नीतगत कारक:** सरकारी नीतियों और कृषि पद्धतियों में बदलाव सहित व्यापक आर्थिक कारक इस गरीबों के योगदानकर्ता हो सकते हैं।
 - उदाहरण के लिये, सब्सिडी, ऋण उपलब्धता या बाजार पहुँच से संबंधित नीतियों में बदलाव नविश नरिणियों को प्रभावित कर सकते हैं।
- **वैश्विक और जलवायु संबंधी कारक:** वैश्विक आर्थिक स्थितियाँ, जलवायु परिवर्तन और अन्य बाह्य कारक भी कृषि और पूंजी नरिमाण को प्रभावित कर सकते हैं। उदाहरण के लिये, बदलते मौसम के पैटर्न से कुछ कृषि नविशों की व्यवहार्यता प्रभावित हो सकती है क्योंकि जलवायु परिवर्तन कृषि को कम लाभप्रदता और तापमान परिवर्तन, कीटों एवं बीमारियों के कारण उच्च फसल वफिलता जोखिम के साथ प्रभावित करता है।

GCAF में इस कमी का क्या असर हो सकता है?

- **धीमी कृषि वृद्धि:** जब पूंजी नरिमाण में गरीब आती है तो कृषि क्षेत्र की वृद्धि की गति सुस्त हो सकती है। ऐसा इसलिए है क्योंकि पूंजी का अर्थ होगा बुनियादी ढाँचे ढाँचे, प्रौद्योगिकी और आधुनिक कृषि पद्धतियों में कम नविश, जो उत्पादकता में सुधार के लिये महत्वपूर्ण हैं।
 - उदाहरण के लिये, भारत में आयोजित एक अध्ययन में पाया गया कि कृषि में सार्वजनिक पूंजी नरिमाण में 10% की वृद्धि से कृषि उत्पादन में 1.6% की वृद्धि हुई।
- **आय असमानता: विश्व बैंक** के अनुसार नमिन-आय देशों में नरिधनतम 40% आबादी की औसत आय वर्ष 2018 में 1.25 डॉलर प्रतिदिन थी, जबकि सबसे अमीर 10% की औसत आय 9.61 डॉलर प्रतिदिन थी। धीमी गति से वृद्धि कर रहा कृषि क्षेत्र इस असमानता को और बढ़ा सकता है।
- **रोज़गार सृजन संबंधी चुनौतियाँ:** कृषि क्षेत्र एक प्रमुख नयिोक्ता है। यदि क्षेत्र धीमी गति से बढ़ता है तो यह खेती और संबंधित उद्योगों में कम रोज़गार सृजति करेगा। इससे ग्रामीण क्षेत्रों में बेरोज़गारी दर या अल्प रोज़गार दर बढ़ सकती है।
- **खाद्य सुरक्षा पर प्रभाव:** FAO के अनुसार विश्व 9.7 बिलियन आबादी का पेट भरने के लिये वर्ष 2050 तक 50% अधिक खाद्य उत्पादन की आवश्यकता होगी। धीमी गति से विकास कर रहा कृषि क्षेत्र इस लक्ष्य में बाधक बन सकता है जिससे भुखमरी एवं कुपोषण का खतरा बढ़ सकता है।
- **प्रतिसिपर्द्धात्मकता में कमी:** यदि भारत के कृषि क्षेत्र में पूंजी नविश की कमी होगी तो विश्व स्तर पर इसकी प्रतिसिपर्द्धात्मकता में कमी आ सकती है।
 - अन्य देश जो अपनी कृषि में अधिक नविश करते हैं, उन्हें दक्षता, प्रौद्योगिकी अंगीकरण और नरियात क्मताओं के मामले में बढ़त प्राप्त हो सकती है।
- **पर्यावरणीय परणाम:** विश्व संसाधन संस्थान (World Resources Institute- WRI) के एक अध्ययन में अनुमान लगाया गया है कि वर्ष 2010 में वैश्विक ग्रीनहाउस गैस उत्सर्जन के 24% के लिये कृषि क्षेत्र ज़िम्मेदार था और यदि मौजूदा रुझान जारी रहा तो यह हसिसेदारी वर्ष 2050 तक 30% तक बढ़ सकती है।
 - कृषि के पर्यावरणीय प्रभाव को कम करने का एक तरीका यह होगा कि कृषि में नमिन-कार्बन और जलवायु-स्मार्ट प्रौद्योगिकियों एवं अभ्यासों का नविश किया जाए।
- **मानसून पर नरिभरता:** इंडियन काउंसिल फॉर रसिर्च ऑन इंटरनेशनल इकोनॉमिक रलेशंस (ICRIER) के एक अध्ययन में पाया गया किमान्य वर्षा से 1% वचिलन से भारत में कृषि विकास में 0.7% की कमी आई।
 - मानसून पर नरिभरता कम करने के लिये सचिाई प्रणाली वकिसति करने, मौसम पूर्वानुमान और फसल बीमा के वषिय में पूंजी नविश की आवश्यकता है।

भारत में कृषि का महत्त्व

- यह कुल जनसंख्या के लगभग 54.6% को रोज़गार के अवसर प्रदान करता है।
- यह कुल सकल घरेलू उत्पाद में लगभग 17% का योगदान देता है।
- यह भारत की वृहत और बढ़ती आबादी के लिये खाद्य की आपूर्ति करता है।
- यह वभिन्न कृषि-आधारित और खाद्य प्रसंस्करण उद्योगों के लिये कच्चा माल उपलब्ध कराता है।
- यह देश के आंतरिक और बाह्य व्यापार एवं वाणज्य को प्रभावित करता है।
- यह पूंजी नरिमाण और सरकारी राजस्व सृजन में मदद करता है।

GCAF को बढ़ावा देने के लिये कौन-सी सरकारी पहलें की गई हैं?

- **कसिन क्रेडिट कार्ड, ब्याज छूट योजना (Interest Subvention Scheme)** आदि जैसी योजनाओं के माध्यम से कसिनों के लिये संस्थागत ऋण की वृद्धि की गई है।
- **ग्रामीण भंडारण योजना, भंडारण विकास एवं वनियामक पराधकिरण (Warehousing Development and Regulatory Authority)** आदि योजनाओं के माध्यम से कृषि उपज के जीवनकाल (शेल्फ लाइफ) को बढ़ाने के लिये वैज्ञानिक भंडारण अवसंरचना को बढ़ावा दिया जा रहा है।
- **प्रधानमंत्री कसिन संपदा योजना, कृषि-बाजार अवसंरचना नधि (Agri-Market Infrastructure Fund)** जैसी योजनाओं के माध्यम से खेती को प्रतिसिपर्द्धी एवं लाभदायक बनाने के लिये एग्री-टेक इंफ्रास्ट्रक्चर फंड की स्थापना की गई है।
- **परंपरागत कृषि विकास योजना, मशिन जैविक मूल्य शृंखला विकास (Mission Organic Value Chain Development)** जैसी योजनाओं के माध्यम से व्यावसायिक जैविक खेती का विकास किया जा रहा है।
- **राष्ट्रीय कृषि विकास योजना, कृषि उदान (Agri Udaan)** जैसी योजनाओं के माध्यम से कृषि और संबद्ध क्षेत्रों में एक स्टार्ट-अप पारितंत्र का नरिमाण किया जा रहा है।

कृषि में GCF बढ़ाने के लिये और क्या किया जाना चाहिये?

- सचिवाई, अनुसंधान एवं विकास, वसितार सेवाओं, बाज़ार अवसंरचना आदिपर सार्वजनिक व्यय बढ़ाना।
 - ये कृषि की उत्पादकता एवं लाभप्रदता में सुधार करने और नज़ी नविश के लिये अनुकूल माहौल बनाने में मदद कर सकते हैं।
- मॉडल कृषि उपज और पशुधन वपिणन अधिनियम (Model Agriculture Produce and Livestock Marketing Act), मॉडल कृषि उपज और पशुधन अनुबंध खेती अधिनियम (Model Agriculture Produce and Livestock Contract Farming Act), कृषि उतपादक कंपनियों (Farmer Producer Companies) को आयकर से छूट जैसे नीतितगत सुधारों के माध्यम से कृषि में नज़ी क्षेत्र की भागीदारी को बढ़ावा देना।
 - ये वैकल्पिक वपिणन चैनल का नरिमाण करने, अनुबंध खेती को सुवधाजनक बनाने और कृषिों द्वारा सामूहिक कार्रवाई को प्रोत्साहित करने में मदद कर सकते हैं।
- जलवायु प्रत्यास्थी और नमिन-उत्सर्जनकारी कृषि की दशिया में रूपांतरण का समर्थन करने के लिये जलवायु वतित की क्षमता का लाभ उठाना। इसे तीन परस्पर-संबंध मार्गों के माध्यम से प्राप्त किया जा सकता है: प्रत्यास्थी कृषि को बढ़ावा देना, जलवायु संबंधी सलाह एवं जोखमि प्रबंधन सेवाओं को सुवधाजनक बनाना और खाद्य प्रणालियों का पुनर्वनियाम करना।
 - हरति जलवायु कोष (GCF) जलवायु वतित के स्रोतों में से एक है जो इन लक्ष्यों को प्राप्त करने में वकिसशील देशों का समर्थन कर सकता है।

नषिकरष:

कृषि में सकल पूंजी नरिमाण में मंदी के कारण भारत को कृषि संवहनीयता में चुनौतियों का सामना करना पड़ रहा है। सार्वजनिक नविश में परिवर्तन और कृषि पिदधतियों में बदलाव से यह समस्या जटिल हो गई है, जिससे आय वतितरण, रोजगार सृजन और वैश्विक प्रतसिप्रद्धात्मकता प्रभावति हो रही है। भारत के महत्त्वपूर्ण कृषि क्षेत्र के प्रत्यास्थी, प्रतसिप्रद्धी और संवहनीय भवषिय के लिये सहयोगात्मक एवं रणनीतिक उपाय आवश्यक हैं।

अभ्यास प्रश्न: भारत में कृषि में सकल पूंजी नरिमाण (GCFA) की मंदी में योगदान देने वाले कारकों और इस मुद्दे को संबोधति करने पर लक्षति सरकारी पहलों की चर्चा कीजिये। कृषि क्षेत्र में पूंजी नरिमाण को बढ़ावा देने के लिये रणनीतिक उपायों के प्रस्ताव कीजिये।

UPSC सविलि सेवा परीक्षा, वगित वर्ष प्रश्न (PYQ)

????????

प्रश्न 1. भारतीय कृषि में परस्थितियों के संदर्भ में, "संरक्षण कृषि" की संकल्पना का महत्त्व बढ़ जाता है। नमिनलखिति में से कौन-कौन से संरक्षण कृषि के अंतरगत आते हैं? (2018)

1. एकधान्य कृषि पिदधतियों का परहार
2. न्यूनतम जोत को अपनाना
3. बागानी फसलों की खेती का परहार
4. मृदा धरातल को ढकने के लिए फसल अवशषिट का उपयोग
5. स्थानिक एवं कालिक फसल अनुक्रमण

नीचे दिये गए कूट का प्रयोग कर सही उत्तर चुनिये:

- (a) 1,3 और 4
- (b) 2,3,4 और 5
- (c) 2, 4 और 5
- (d) 1, 2,3 और 5

उत्तर: (c)

प्रश्न 2. जलवायु-अनुकूल कृषि (क्लाइमेट-स्मार्ट एग्रीकल्चर) के लिये भारत की तैयारी के संदर्भ में, नमिनलखिति कथनों पर वचिर कीजिये-

1. भारत में 'जलवायु-स्मार्ट ग्राम (क्लाइमेट-स्मार्ट वल्लिज)' दृषटिकोण, अंतरराष्ट्रीय अनुसंधान कार्यक्रम-जलवायु परिवर्तन, कृषि एवं खाद्य सुरक्षा (सी.सी.ए.एफ.एस.) द्वारा संचालति परियोजना का एक भाग है।
2. सी.सी.ए.एफ.एस. परियोजना, अंतरराष्ट्रीय कृषि अनुसंधान हेतु परामर्शदात्री समूह (सी.जी.आई.ए.आर.) के अधीन संचालति किया जाता है, जिसका मुख्यालय पेरिस में है।
3. भारत में स्थिति अंतरराष्ट्रीय अर्धशुष्क उषणकटबिंधीय फसल अनुसंधान संस्थान (आई.सी.आर.आई.एस.ए.टी.), सी.जी.आई.ए.आर. के अनुसंधान केंद्रों में से एक है।

उपर्युक्त कथनों में से कौन-से सही हैं?

- (a) केवल 1 और 2
- (b) केवल 2 और 3
- (c) केवल 1 और 3
- (d) 1, 2 और 3

उत्तर:(d)

??????

प्रश्न 1. उन वभिन्न आर्थिक और सामाजिक-सांस्कृतिक ताकतों पर चर्चा कीजिये जो भारत में कृषि के बढ़ते नारीकरण को प्रेरित कर रही हैं। (2014)

प्रश्न 2. फसल विविधीकरण के समक्ष वर्तमान चुनौतियाँ क्या हैं? उभरती प्रौद्योगिकियाँ फसल विविधीकरण का अवसर कैसे प्रदान करती हैं? (2021)

PDF Refernece URL: <https://www.drishtias.com/hindi/printpdf/agricultural-capital-decline-unveiling-causes-and-cures>

